सुरजीत सिंह एवं अन्य।

बनाम

गुरवंत कौर एवं अन्य।

(2014 की सिविल अपील संख्या 8283)

27 अगस्त 2014

[दीपक मिश्रा और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XLI r.27 - विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा - अनुस्मारक के बावजूद वादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए - अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए वादी द्वारा आवेदन ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया जिसे पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अभ्यास में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है - मुकदमा खारिज होने के बाद, वादी द्वारा अपील में, अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पास बुक और बैंक खातों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए OR.XLI r.27 के तहत आवेदन दायर किया गया - ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन की अनुमति दी गई उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को बरकरार रखा गया, चुनौती दी गई- माना गया: दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए दिए गए कई अवसरों के बावजूद, वादी ने इसका लाभ नहीं उठाया, और इसलिए, उक्त दस्तावेज़ों को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया-सिविल पुनरीक्षण दायर किया गया और गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया। -

दस्तावेजों के समान सेट को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी - जिन दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष दाखिल करने की मांग की गई थी, वे बैंक खाते थे जो वास्तव में विवाद खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थे - Or.XLI r. 27(1)(बी) आकर्षित नहीं होता है इसलिए, अपीलीय अदालत ने उक्त खंड का सहारा लेकर और अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए आवेदन की अनुमति देकर गलती की है।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए

1. यह अदालत का कर्तव्य है कि वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए दस्तावेजों को अतिरिक्त सबूत के रूप में स्वीकार करना वास्तव में आवश्यक है। सच्ची परीक्षा वहीं है जहां एक अपीलीय अदालत मांगे गए अतिरिक्त सबूतों पर विचार किए बिना अपने समक्ष मौजूद सामग्रियों के आधार पर निर्णय सुनाने में सक्षम थी। मौजूदा मामले में, दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वादी ने बी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। इसलिए, उक्त दस्तावेज़ों को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। एक नागरिक पुनरीक्षण दायर किया गया और गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष दस्तावेजों का वही सेट पेश करने की मांग की गई थी। उक्त दस्तावेज़ निर्णायक हैं और

वास्तव में निर्णय की घोषणा के लिए या उस मामले के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए आवश्यक हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सार्वजनिक दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचाराधीन मुकदमे पर निर्णय न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा और न्याय के गर्भपात से बचाएगा। मौजूदा मामले में, अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज़ बैंक खाते थे जो वास्तव में विवाद खड़ा करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। आदेश एक्सएलआई नियम 27 (1) (बी) के तहत मामले को यह सुझाव देना बेहद मुश्किल है कि न्याय के हित में दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त, जब उक्त दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया था तो उन्हें लिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड और उक्त अस्वीकृति की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इसलिए, अपीलीय अदालत ने उक्त खंड का सहारा लेने और अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए आवेदन की अनुमति देने में गलती की है और इसी तरह एफ उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अवैधता की है कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश किसी भी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।

पारसोतिम बनाम लाल मोहन एआईआर 1931 पीसी 143; अर्जन सिंह जी बनाम करतार सिंह और अन्य। एआईआर 1951 एससी 193 पर भरोसा किया।

अर्जुन सिंह वि. मोहिन्द्र कुमार एवं अन्य। एआईआर 1964 एससी 993: 1964 एससीआर 946; कुन्हायमद और अन्य वी. केरल राज्य और अन्य. (2000) 6 एससीसी 359: 2000 (1) पूरक। एससीआर 538; शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम. कृष्णाजी दत्तात्रेय बपेट (1969) 2 एससीसी 74: 1970 (1) एससीआर 322; के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीतारमा रेड्डी और अन्य। एआईआर 1963 एससी 1526: 1964 एससीआर 35; सैयद अब्दुल खादर बनाम रामी रेड्डी और अन्य, एआईआर 1979 एससी 553; बिल्ला जगन मोहन रेड्डी और अन्य बनाम बिल्ला संजीव रेड्डी और अन्य। (1994) 4 एससीसी 659: 1994 (1) एससीआर 429; वादी बनाम अमीलाल और अन्य। जेटी 2002 (6) एससी 16 प्रतिष्ठित।

सत्यधन घोषाल और अन्य। वी. श्रीमती देवराजिन देबी और अन्य। एआईआर 1960 एससी 941: 1960 एससीआर 590; मोहेशूर सिंह बनाम बंगाल सरकार 7 मू इंडस्ट्रीज़ ऐप 283 पृष्ठ पर। 302 (पीसी); फोर्ब्स बनाम अमीरूनिसा बेगम 10 मू इंडस्ट्रीज़ ऐप 340 (पीसी); श्योनाथ बनाम रामनाथ 10 मू इंड ऐप 431 (पीसी); यूनाइटेड प्रोविंसेस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इलाहाबाद बनाम देयर वर्कमेन (1972) 2 एससीसी 54; एस. मल्ला रेड्डी बनाम फ्यूचर बिल्डर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अन्य। (2013) 9 एससीसी 349: 2013 (6) एससीआर 230 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1964 एससीआर 946

2000 (1) पूरक। एससीआर 538

1970 (1) एससीआर 322

1964 एससीआर 35

एआईआर 1979 एससी 553

1994 (1) एससीआर 429

जेटी 2002 (6) एससी 16

1960 एससीआर 590

7 मू इंडस्ट्रीज़ ऐप (पीसी) 283 पी पर। 302

10 मू इंडस्ट्रीज़ ऐप 340 (पीसी)

10 मू इंड ऐप 431 (पीसी)

ए (1972) 2 एससीसी 54

2013 (6) एससीआर 230

एआईआर 1931 पीसी 143

एआईआर 1951 एससी 193

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या 8283। 2011 के सीआर संख्या 5850 (ओ एंड एम) में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.05.2012 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से मंजुला गुप्ता।

विकास महाजन, विशाल महाजन, ए.एन. प्रतिवादियों की ओर से सिंह, भास्कर वाई. डी. कुलकर्णी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक मिश्रा, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने और अपीलकर्ता नंबर के बीच हुए अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पट्टी, जिला तरनतारन की अदालत में सिविल सूट नंबर 78/2003 स्थापित किया। 1, अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 और एफ प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्ववर्ती-हित में 28 के 12 मीटर की भूमि की बिक्री के लिए खाता खतौनी 330/1254, 1256, 331/1261 और किला संख्या 34/25 शामिल है। (712), 40/1/1 (4-15), 10/2 मिनट (0-8), 41/5 मिनट (2-8) 6/1 (7-5) 15/1 (2-16) , 34/162 (3-8), गांव तलवंडी सोभा सिंह तहसील पट्टी जिला अमृतसर में स्थित है, वर्ष 1997-98 की

जमाबंदी के अनुसार 3,22,500/- रुपये प्रति किला की दर से जो इसमें भूमि से जुड़े सभी अधिकार शामिल थे।

3. वादपत्र में कहा गया था कि सिविल मुकदमे में प्रतिवादी को 7.2.2003 को 50,000/- रुपये और अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी। 25.2.2003 को 50,000/- जबकि समझौते के अनुसार निर्धारित मूल्य एच 3,22,500/- प्रति किला था। जैसा कि निर्धारित है समझौते में शेष राशि का भुगतान 3.6.2013 को उप रजिस्ट्रार, पट्टी के समक्ष बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय किया जाना था। समझौते में यह भी कहा गया था कि वाद की भूमि पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास गिरवी है और प्रतिवादियों को वादी के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले ऋण का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। वादी, जैसा कि वाद में कहा गया है, उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में गया लेकिन प्रतिवादी नहीं आये। चूंकि प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि वे वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करने में विफल रहे, उन्होंने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए या वैकल्पिक रूप से 2,00,000/- रुपये की वसूली के लिए नागरिक कार्रवाई शुरू की। मुआवज़े के रूप में.

4. प्रतिवादियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और लिखित आवेदन दाखिल किया। अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देने वाला बयान कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है; कि वादी शेष राशि के साथ तैयार नहीं था। मात्रा; वादी द्वारा रखा गया यह रुख कि वह 3.6.2003 को शेष बिक्री के विचार और गवाहों के साथ तहसील परिसर में आया था, सच्चाई से बहुत दूर था, क्योंकि मूल प्रतिवादी सब रजिस्ट्रार, पट्टी के कार्यालय में मौजूद थे। प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक लेकिन वादी उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि वह शेष प्रतिफल के साथ तैयार नहीं था; और प्रतिवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संबंधित उप-रजिस्ट्रार के समक्ष एक आवेदन दिया और एक हलफनामा दिया जिस पर उप-रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिवादियों का आगे का रुख यह था कि वादी और उसके रिश्तेदारों ने विवाद में संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप धारा 307, 326, 323, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर संख्या 97 दिनांक 9.6.2003 दर्ज की गई। भारतीय दण्ड विधान की धारा 25 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 पंजीकृत किया गया।

5. विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने छह मुद्दों को तय किया, साक्ष्य दर्ज किए और अंततः वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी ने धारा के तहत एक आवेदन दायर किया था, अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल

करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 इस प्रार्थना के साथ कि उक्त दस्तावेज़ों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आवेदन में कहा गया था कि अपने साक्ष्य में उसने पहले ही बता दिया था कि उसे अपने पति के भाई जियान बी सिंह से 9,00,000/- रुपये मिले थे, और उसके खाते में 1,00,000/- रुपये थे। 1313. यह भी कहा गया कि वह इस धारणा के तहत थी कि उसके पिता मामले की पैरवी कर रहे थे और उन्होंने ज्ञान सिंह के खाते का विवरण क्रमांक 1-29 और वादी के क्रमांक एसबी/17274 दाखिल किया था, लेकिन अनजाने में उसके पिता ऐसा कर सके। उसने खातों और पासबुक का उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त पृष्ठभूमि में दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए प्रार्थना की गई थी।

6. विद्वान ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> "फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि मुकदमा 23.7.2003 को दायर किया गया था और मुद्दे 7.1.2004 को तय किए गए थे। तब से, वादी ने अपने साक्ष्य पेश करने और निष्कर्ष निकालने के लिए 14 अवसरों का लाभ उठाया और अंततः 11.5.05 को और उसके बाद इसे अपने हिसाब से बंद कर दिया। मामला प्रतिवादी के साक्ष्य के

लिए तय किया गया था। प्रतिवादी ने भी अपने साक्ष्य को समाप्त करने के लिए 19 अवसर लिए और अंततः 19.4.06 को इसे बंद कर दिया और उसके बाद मामला वादी के खंडन साक्ष्य के लिए तय किया गया, जिसके लिए वादी ने 8 अवसर लिए और फिर वह सामने आया। वर्तमान आवेदन के साथ। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह महज असावधानी नहीं थी कि ये प्रतियां वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकीं, बल्कि वादी ने स्वयं परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया। यदि आवेदक मेहनती था, तो आवेदन आना चाहिए था रिकॉर्ड, बहुत पहले और अब नहीं और यह केवल समय मांगने और कमियां भरने का प्रयास प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदन खारिज किया जाता है।"

7. उपरोक्त आदेश को सिविल रिवीजन संख्या में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 का 6014 और विद्वान एकल न्यायाधीश ने, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने के बाद, निम्नलिखित कारण बताते हुए सिविल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया: -

"ऊपर उल्लिखित आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से खातों के

विवरण की प्रतियां पेश करने का एक अवसर देने के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि वादी ने कई अवसरों का लाभ उठाया, लेकिन अपने मामले के समर्थन में खाते के विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करने में विफल रही। अन्यथा भी, मामला अंतिम चरण में है और अब यह आवेदन उसके मामले के समर्थन में उपरोक्त संदर्भित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए है। केवल मामले की कार्यवाही में देरी करने के लिए दायर किया गया है। इसके अलावा, खातों के विवरण की उपरोक्त प्रतियां वादी-याचिकाकर्ता की जानकारी में थीं और यदि याचिकाकर्ता सतर्क थी, तो उसे उचित चरण में इसे प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से खाते के विवरण की प्रतियां पेश करने के आवेदन को खारिज करने में विद्वान ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता है, जो इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

8. इसके बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी और, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसे खारिज कर दिया गया। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से दुखी होकर, वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तरनतारन के समक्ष अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी-अपीलकर्ता ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पासबुक और बैंक खातों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन का कई आधार

पर विरोध किया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने माना कि साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति का है और स्वीकार्य है, इसलिए इसकी अनुमति देना उचित है। निचली अपीलीय अदालत ने भी देखा कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों को इसका खंडन करने का अवसर मिलेगा। इस दृष्टिकोण से उन्होंने लागत के रूप में 1,000/- रुपये के भुगतान की शर्त पर आवेदन की अनुमति दी।

9. उक्त आदेश को 2011 के सिविल रिवीजन नंबर 5850 में खारिज कर दिया गया था और दिनांक 3.5.2012 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि निचली अपीलीय अदालत ने कानून में प्रावधानों की काफी सराहना की थी और सही राय दी थी कि मामले के न्यायसंगत निर्णयों के लिए दस्तावेज़ों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए एक मुकदमे में वादी की अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने की तैयारी और इच्छा, एक महत्वपूर्ण कारक है, आवेदन की अनुमति देकर निचली अपीलीय अदालत ने कोई कानूनी अपराध नहीं किया है। दुर्बलता उक्त आदेश विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील में विचाराधीन है।

10. आदेश की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मंजुला गुप्ता ने आग्रह किया है कि

एक बार अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन को विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसी पर मुहर लग गई थी। ई पर हमला होने पर सिविल पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के बाद, उक्त आदेश पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करता है और इसलिए, निचली अपीलीय अदालत आवेदन पर विचार नहीं कर सकती थी। विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायाधीश न केवल अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में गंभीर त्रुटि में पड़ गए हैं, बल्कि एफ रेडी और इच्छा से संबंधित याचिका को ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और निपुणता के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। वादी/अपीलकर्ताओं द्वारा अपीलीय स्तर पर खातों की किताबें प्रस्तुत करने के लिए यह दिखाने के लिए कि उनके खातों में पैसा था, दायरे में नहीं आएगा और सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत मामला बनाने के लिए स्वीप किया जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त प्रावधान के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जिन सामग्रियों को पूरा करना आवश्यक है, वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और इसलिए, विवादित आदेश बिल्कुल असुरक्षित है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने अर्जुन सिंह बनाम मोहिंदरा मामले के निर्णयों के लिए हमारी सराहना की है कुमार और अन्य, कुन्हायमद और अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य तथा शंकर रामचन्द्र अभ्यंकर बनाम। कृष्णाजी दत्तात्रेय बपेट.

11. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विकास महाजन तर्क देंगे कि पहला आवेदन सीपीसी की धारा 151 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए दायर किया गया था और जब अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए आवेदन किया जाता है तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत साक्ष्य अपीलीय अदालत के समक्ष दायर किया जाता है। उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि उक्त दस्तावेजों को स्वीकार करने से न्याय का उद्देश्य पूरा होगा और जब अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के रुख को उचित परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर लिया है, तो लगाए गए आदेशों में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त दलील को मजबूत करने के लिए उन्होंने के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीतारमा रेड्डी और अन्य, सैयद अब्दुल खादर बनाम रामी रेड्डी और अन्य, बिल्ला जगन मोहन रेड्डी और अन्य बनाम बिल्ला संजीव रेड्डी और अन्य और वाडी बनाम के फैसलों पर भरोसा किया है। .अमीलाल व अन्य।

12. सबसे पहले, हम उस आवेदन से निपटेंगे जो वादी द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया था। यह अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन था और विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया। उक्त आदेश को सिविल

पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि जब विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसे आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी

1. एआईआर 1964 एससी 993।

2. (2000) 6 एससीसी 359।

3. (1969) 2 एससीसी 74.

4. एआईआर 1963 एससी 1526।

5. एआईआर 1979 एससी 553।

6. (1994) 4 एससीसी 659।

7. जेटी 2002 (6) एससी 16।

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का एक अभ्यास, क्या सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत शक्ति के प्रयोग में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए प्रथम अपीलीय अदालत की ओर से औचित्य की दृष्टि से अभी भी अनुमति दी जाएगी और यदि नहीं, तो क्या यह कर्तव्य नहीं था इसे स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय।

13. इस संदर्भ में, हम सत्यधन घोषाल और अन्य बनाम श्रीमती मामले में प्राधिकारी को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं। देवराजिन

देबी और अन्य। यह एक ऐसा मामला था जहां मकान मालिकों ने किरायेदारों के खिलाफ बेदखली का फरमान प्राप्त कर लिया था। डिक्री जारी होने के बाद, कलकत्ता थिका किरायेदारी अधिनियम, 1949 लागू हुआ। डिक्री को अभी तक निष्पादन के लिए नहीं रखा गया था। किरायेदारों ने उनके खिलाफ पारित डिक्री को रद्द करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन का उन जमींदारों द्वारा विरोध किया गया जो डिक्री धारक थे। विद्वान मुंसिफ ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। डी को यह बताते हुए कि किरायेदार थिका किरायेदारी अधिनियम के तहत थिका किरायेदार थे। उक्त आदेश के खिलाफ किरायेदारों ने सीपीसी की धारा 115 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। जब तक पुनरीक्षण आवेदन सुनवाई के लिए लिया गया, तब तक कलकत्ता थिका किरायेदारी अधिनियम 1953 में संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम ने मूल अधिनियम की ई धारा 28 को हटा दिया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम में किए गए संशोधन के प्रभाव पर विचार किया और राय दी कि "थिका किरायेदार" शब्द की संशोधित परिभाषा और रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के मद्देनजर यह माना जा सकता है कि किरायेदार थिका किरायेदार थे। इस दृष्टिकोण के आधार पर, उच्च न्यायालय ने एफ को पुनरीक्षण की अनुमति दी और विद्वान मुंसिफ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उन्होंने अधिनियम की धारा 28 के तहत किरायेदारों के आवेदन को खारिज कर दिया था। आदेश को रद्द करने

के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को कानून के अनुसार निपटाने के लिए विद्वान मुंसिफ की अदालत में भेज दिया। विवेचक मुंसिफ जी ने माफी के बाद डिक्री को रद्द कर दिया। उक्त आदेश को सीपीसी की धारा 115 के तहत चुनौती दी गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पुनरीक्षण में, एक तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 28 लागू नहीं थी। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि दोनों पक्षों के बीच प्रश्न एच 8. एआईआर 1960 एससी 941 था।

न्याय. उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। उस संदर्भ में, न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया: -

"पुनर्न्याय का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। यह क्या कहता है कि एक बार जब मुक़दमा न्यायिक हो जाता है, तो उस पर दोबारा निर्णय नहीं दिया जाएगा.. मुख्य रूप से यह पिछले मुकदमे और भविष्य के मुकदमे के बीच लागू होता है। जब कोई मामला चाहे तथ्य के प्रश्न पर हो - या कानून के प्रश्न पर एक मुकदमे या कार्यवाही में दो पक्षों के बीच तय किया गया हो और निर्णय अंतिम है, या तो उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई थी या अपील खारिज कर दी गई थी, या नहीं अपील निहित है, किसी भी पक्ष को भविष्य के मुकदमे में या मामले के लाभ के लिए समान पक्षों के बीच

कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया का यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में मुकदमों के संबंध में सन्निहित है; लेकिन यहां तक कि जहां एस 11 लागू नहीं होता है, मुकदमे में अंतिम निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से अदालतों द्वारा पूर्व न्यायिकता का सिद्धांत लागू किया गया है। इसका नतीजा यह है कि मूल अदालत के साथ-साथ किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी भविष्य के मुकदमे में इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए पिछला निर्णय सही था.

ऐसा कहने के बाद न्यायालय ने मुकदमे के दो चरणों के बीच पुनर्न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता का सिद्धांत निर्धारित किया: -

> "पुनर्न्याय का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो चरणों के बीच भी इस हद तक लागू होता है कि एक अदालत, चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो या उच्च न्यायालय, पहले चरण में किसी मामले का एक तरह से फैसला करने के बाद, पार्टियों को दोबारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी। उसी कार्यवाही के बाद के चरण में मामले को फिर से उत्तेजित करें। क्या इसका मतलब यह है कि क्योंकि मुकदमेबाजी के पहले चरण में एक अदालत ने एक अंतरिम मामले का एक तरह से फैसला किया है और वहां कोई अपील नहीं की गई है या कोई अपील नहीं हुई है, ए उच्च न्यायालय उसी

मुकदमे के बाद के चरण में मामले पर दोबारा विचार नहीं कर सकता?"

ए उक्त प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने मोहेशुर सिंह बनाम बंगाल सरकार, फोर्ब्स बनाम अमीरूनिसा बेगम 10 और श्योनाथ बनाम रामनाथ[11] में प्रिवी काउंसिल के फैसलों की जांच की और मोहेशुर सिंह (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने बी. इस प्रकार आयोजित किया गया:-

"हमारी राय है कि इस आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है। हम भारत में प्रचलित किसी भी कानून या विनियम के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि प्रत्येक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए मुकदमा दायर करने वाले को अनिवार्य बनाता है, जिसके द्वारा वह दंड के तहत खुद को पीड़ित मान सकता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है, अपीलीय अदालत के विचार के लाभ को हमेशा के लिए जब्त कर लेता है। ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में किसी अधिकार या मिसाल का हवाला नहीं दिया गया है, और हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि न्याय के शीघ्र प्रशासन के लिए कुछ भी अधिक हानिकारक होगा एक ऐसे नियम की स्थापना की तुलना में जो प्रेमी पर इतनी अपील की

आवश्यकता को लागू करेगा; जिससे एक तरफ उसे अंतहीन खर्च और देरी से परेशान किया जा सकता है, और दूसरी तरफ उसके प्रतिद्वंद्वी पर समान आपदाएं आ सकती हैं। हमारा मानना है कि बहुत कुछ हुआ है इस न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसे कई मामले हैं जिनमें उनके आधिपत्य ने गलत अंतर्वर्ती आदेशों को ठीक करना अपना कर्तव्य समझा है, हालांकि पूरे कारण का निर्णय होने तक उन्हें अपने विचाराधीन नहीं लाया गया था, और न्यायनिर्णयन के लिए अपील द्वारा यहां लाया गया था।"

उक्त सिद्धांत को मंजूरी देते हुए इस न्यायालय ने कहा कि उस मामले में अपीलकर्ताओं को यह सवाल उठाने से नहीं रोका गया था कि मूल थिका किरायेदारी अधिनियम की धारा 28 थिका किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1953 के लागू होने के बाद किरायेदारों के लिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा एक अपील थी।

7 मू इंड ऐप 283 पी पर। 302 (पीसी)।

10 मू इंड ऐप 340 (पीसी)। एच 11.10 मू इंड ऐप 431 (पीसी)।

14. अर्जुन सिंह ए में उपरोक्त निर्णय का अनुमोदन किया गया (सुप्रा) जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया: -

"यदि पहला निर्णय देने वाली अदालत मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने के लिए सक्षम थी, और इसलिए मुद्दे या मामले पर निर्णय लेने की क्षमता रखती थी, तो यह परिस्थिति कि यह विशेष क्षेत्राधिकार वाला न्यायाधिकरण है या जिसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। बाद की कार्यवाहियों में न्यायिक निर्णय होने के कारण इस मुद्दे के निष्कर्ष स्वयं नकारात्मक हैं। इसी तरह, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 स्पष्ट रूप से दो मुकदमों के अस्तित्व पर विचार करती है और पहले में निष्कर्ष न्यायिक निर्णय में हैं। बाद के मुकदमे में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इसमें अंतर्निहित सिद्धांत एक ही मुकदमे या कार्यवाही के क्रमिक चरणों में दिए गए निर्णयों के मामले में समान रूप से लागू होता है। लेकिन जहां कार्यवाही के विभिन्न चरणों के मामले में पुनर्न्याय का सिद्धांत लागू किया जाता है एक ही मुकदमा, कार्यवाही की प्रकृति, जांच का दायरा जो विशेषण कानून निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रदान करता है, साथ ही ऐसे निर्णय से संबंधित मामलों पर किए गए विशिष्ट प्रावधान कुछ ऐसे भौतिक और प्रासंगिक कारक हैं

जिन पर पहले विचार किया जाना चाहिए। सिद्धांत लागू माना जाता है।"

15. इसके बाद, न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ पारित एक पक्षीय आदेशों को रद्द करने के लिए तीन मुकदमों में दायर किए गए आवेदनों पर विचार किया, और आदेश की प्रकृति पर विचार-विमर्श करने के बाद, यानी आदेश IX नियम 7 के तहत एक और अस्वीकृति ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि, आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल करना और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक और उसकी सहमति के आधार पर उसे खारिज करना, अदालत ने सत्यधन में निर्णय का उल्लेख किया घोषाल (सुप्रा) और उसी से एक पैराग्राफ को पुन: प्रस्तुत करने के बाद, इस प्रकार राय व्यक्त की: -

"हालांकि, इसका मतलब यह है कि क्योंकि मुकदमेबाजी के पहले चरण में एक अदालत ने एक अंतरिम मामले का फैसला किया है

एक तरह से और वहां कोई अपील नहीं की गई है या कोई अपील नहीं हुई है, एक उच्च न्यायालय उसी मुकदमे के बाद के चरण में मामले पर दोबारा विचार नहीं कर सकता है? इसलिए यह स्पष्ट है कि एक अंतरिम आदेश जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई थी क्योंकि या तो कोई

अपील नहीं हुई थी या भले ही अपील की गई थी लेकिन अपील नहीं की गई थी, उसे अंतिम डिक्री या आदेश से अपील में चुनौती दी जा सकती है।"

16. इतना कहने के बाद, न्यायालय ने पाया कि यदि अपीलकर्ता द्वारा दायर आदेश IX नियम 7 के तहत आवेदन के निपटान में सिविल जज के आदेश की शुद्धता पर मुकदमे में डिक्री के खिलाफ अपील में सवाल उठाया गया था, तो ये सिद्धांत और टिप्पणियों की तत्काल प्रासंगिकता होगी। उस संदर्भ में, तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ विभिन्न प्रकार के अंतरिम आदेशों से निपटने के लिए आगे बढ़ी और राय दी कि कुछ आदेश जो प्रकृति में अंतरिम हैं, उसी राहत के लिए बाद के आवेदनों द्वारा बदले या भिन्न किए जा सकते हैं, आमतौर पर केवल नए के प्रमाण पर तथ्य या नई स्थितियाँ जो बाद में सामने आती हैं। न्यायालय ने आदेश की प्रकृति पर जोर दिया और फैसला सुनाया कि यदि यह मुकदमे के पक्षकारों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है तो ई रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत उन निष्कर्षों पर लागू नहीं होगा जिनके आधार पर आदेश पारित किया गया है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि यदि अदालत द्वारा एक बार निपटाए जाने के बाद उसी आधार पर राहत के लिए आवेदन किए गए थे, तो इसे अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में खारिज करना उचित होगा। इसके बाद, एफ कोर्ट ने कहा कि समान तथ्यों के आधार पर लगातार आवेदन, यदि वे अलग-अलग प्रकृति के अंतरिम आदेश हैं और

संपत्ति के संरक्षण के लिए पारित किए गए हैं, तो किसी भी तरह से विवाद की योग्यता का फैसला नहीं करते हैं।

उन्हें जी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर खारिज किया जा सकता है, लेकिन न्यायिक सिद्धांत के आधार पर नहीं। उक्त सिद्धांत का पालन द यूनाइटेड प्रोविंसेज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इलाहाबाद बनाम देयर वर्कमेन[12] और एस. मल्ला रेड्डी बनाम फ्यूचर बिल्डर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अन्य[13] में किया गया था।

(1972) 2 एससीसी 54.

(2013) 9 एससीसी 349।

17. वर्तमान मामले में, हम इस दलील से निपटने का इरादा नहीं रखते हैं कि मुकदमे के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक आवेदन की अस्वीकृति और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक पुनरीक्षण में उसकी पुष्टि न्यायिक न्याय के रूप में कार्य करेगी या नहीं, जब किसी आवेदन को सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के तहत प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रावधान अलग होते हैं। लेकिन, हम तत्काल मामले के विशेष तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संबंध में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग और औचित्य की वैधता से निपटने का इरादा रखते हैं।

18. इस समय, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऑर्डर एक्सएलआई नियम 27 का उप-नियम (1)(ए) मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है

क्योंकि दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था और त्रुटि हुई थी। यदि कोई हो, तो उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक पुनरीक्षण में उस पर अनुमोदन की मुहर लगाने के बाद उक्त आदेश पुनर्विचार के लिए जीवित नहीं रहता है। इसी प्रकार, उप-नियम (1) (एए) लागू नहीं होगा क्योंकि पक्ष इस आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद नहीं हो सका। , उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब डिक्री पारित होने के खिलाफ अपील की गई थी, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी। उप-नियम (1)(बी) के तहत ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, जहां अपीलीय अदालत को फैसला सुनाने में सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य ठोस कारण के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह से पूछताछ करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, उक्त शक्ति का प्रयोग नियम की भाषा में निर्दिष्ट सीमाओं द्वारा सीमित है। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए दस्तावेजों को अतिरिक्त सबूत के रूप में स्वीकार करना वास्तव में आवश्यक है। सच्ची परीक्षा यह है, जैसा कि पारसोतिम बनाम लाल मोहन[1] में हुआ था, जहां अपीलीय अदालत पेश किए जाने वाले अतिरिक्त सबूतों पर विचार किए

बिना अपने सामने मौजूद सामग्रियों के आधार पर निर्णय सुनाने में सक्षम थी। इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है

अर्जन सिंह बनाम करतार सिंह और अन्य 15 में

19. तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले की बात आते ही, मुकदमे की सुनवाई के चरण में दस्तावेजों को पेश करने की मांग की गई। दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वादी पक्ष ने इसका लाभ नहीं उठाया। इसलिए, उक्त दस्तावेज़ों को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। एक नागरिक पुनरीक्षण दायर किया गया और गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष दस्तावेजों का वही सेट पेश करने की मांग की गई थी। उक्त दस्तावेज़ ऐसे दस्तावेज़ नहीं हैं जो निर्णय सुनाने या उस मामले के लिए किसी अन्य ठोस कारण के लिए निर्णायक और वास्तव में आवश्यक हों। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सार्वजनिक दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचाराधीन मुकदमे पर निर्णय न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा और न्याय के गर्भपात से बचाएगा। मौजूदा मामले में, जिन दस्तावेजों को अतिरिक्त सबूत के रूप में अपीलीय अदालत के समक्ष दाखिल करने की मांग की गई है, वे बैंक खाते हैं जो वास्तव में विवाद खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि हम पाते हैं, मामले को आदेश एक्सएलआई नियम 27 (1)(बी) के तहत यह सुझाव देना बेहद मुश्किल है कि जब उक्त

दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर लेने के लिए खारिज कर दिया गया था और उक्त को लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति की पुष्टि की गई थी। हम सचेत हैं, आदेश एक्सएलआई नियम 27 (1)(बी) के तहत कवर किया जा सकने वाला स्पेक्ट्रम व्यापक एफ वन में हो सकता है लेकिन कुछ मामलों में न्यायिक औचित्य एक बाधा होगी और वर्तमान मामला ऐसा है जहां न्यायिक औचित्य आता है। रास्ता। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलीय अदालत ने उक्त खंड का सहारा लेकर और अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जी के आवेदन को अनुमति देकर गलती की है और इसी तरह उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अवैधता की है कि निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश लागू नहीं होता है। किसी दुर्बलता से पीड़ित होना।

न्याय के हित में रिकॉर्ड पर ई दस्तावेज़ और, इसके अतिरिक्त,

20. जैसा कि कहा गया है, विद्वान वकील ने कुछ का उल्लेख किया है प्राधिकरण जो सीपीसी के आदेश एक्सएलआई नियम 27 के दायरे से संबंधित हैं, लेकिन वे तथ्यों पर भिन्न हैं क्योंकि वे उचित परिश्रम, दस्तावेजों की प्रासंगिकता और अपेक्षित दृष्टिकोण से संबंधित हैं। हम पहले ही राय दे चुके हैं कि आदेश एक्सएलआई नियम 27(1)(बी) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए दस्तावेज़ इतने विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि न्यायिक औचित्य एक

बाधा बन जाता है और इसलिए, विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त अधिकारियों को.

21. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, अपील की अनुमति दी जाती है और निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। सी लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति.

हिन्दी अनुवादक -रीतु चौधरी (UID NO RJ-00749)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **रीतु चौधरी** (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।